(d) whether the current annual ceiling of 1.5 billion on external commercial borrowings (ECB) for the power sector is considered too meagre to meet the sec tor's requirements; and

(e) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTER OF POWER (SHRIMATI URMILA BEN CHIMANBHAI PATEL): (a) and (b) No. Sir.

(c) Does not arise.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

मध्य प्रदेश से रूई का निर्यात

5386. श्री द्वितीय सिंह जूदेव: क्या वस्त्र मंत्री 16 अगस्त, 1994 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 2825 के किये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1994-95 के दौरान और चालू वर्ष में मध्य प्रदेश से कितनी रूई का निर्यात किया गया है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी): भारतीय कपास निगम ने अप्रेल, 94 मार्च, 95 के दौरान मध्य प्रदेश से कपास की 2250 गांठों का निर्यात किया।

सिले सिलाये वस्त्रों का निर्यात

5387. श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:
श्री अनन्तराव देवशंकर दवे:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1995-96 के दौरान देश के विभिन्न राज्यों, विशेषकर गुजरात से सिले सिलाये वस्त्रों के निर्यात के लिए कोई सुनियोजित कार्यक्रम तैयार किया है और लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है और राज्य सरकार द्वारा क्या-क्या सुझाव दिये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी): (क) से (ग) वर्ष 1995-96 के लिए देश से सिले सिलाये परिधानों के निर्यात के लिए 4.8 बिलियन अमरीकी डालर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य-वार निर्यात लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते हैं और परिधानों के निर्यात के लिए राज्य-वार योजनाएं भी नहीं बनाई जाती है। तथापि, परिधानों के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है, जिसमें क्रेता-विक्रेता बैठकों, मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए निर्यातकों को प्रोत्साहन देना, निर्यात उत्पादन के लिए रियायती शुल्क पर पूंजीगत माल के निर्यात को सुकर बनाना, निर्यात उत्पादन के लिए कच्चे माल के शुल्क मुक्त आयात के लिए विशेष प्रबंध, निर्यात ऋण की बढ़ती हुई उपलब्धता सुनिश्चित करना आदि शामिल है।

रूई की जमाखोरी

5388. श्री गोपाल सिंह जी॰ सोलंकी: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में, विशेष रूप से गुजरात में, रूई की जमाखोरी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो कितनी रूई की जमाखोरी की गयी है; और

(ग) इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं और रूई के जमाखोरों के विरुद्ध क्या दांडिक कार्रवाई की गयी है या किये जाने का विचार है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी): जी, नहीं। इस समय इस प्रकार की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पटसन उद्योग के संबंध में प्रतिवेदन

5389. श्री ईश दत्त यादव:
श्री कल्याणसिंह चौहानसिंह बंगरोला:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उच्च स्तरीय प्राक्कलन समिति ने पटसन उद्योग के संबंध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है और समिति की मुख्य सिफारिशें कौन-कौन सी हैं;

(ग) उक्त समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी): (क) से (घ) सरकार ने पटसन क्षेत्र की मौजूदा परिस्थितियों का अध्ययन करने तथा नीतियों तथा नीतिपरक उपायों की सिफारिश करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति की स्थापना की थी ताकि उसका आधुनिकीकरण, विविधीकरण किया जा सके तथा निर्यात में वृद्धि की जा सके। इस संपति में नवंबर, 1992 में सरकार को अपने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। उच्च शक्ति प्राप्त समिति की सिफारिशों में विशेष महत्व इस बात पर दिया गया है कि पटसन क्षेत्र का भविष्य विविधीकृत अंत प्रयोगों में एक फाइबर के रूप में पटसन की पूर्ण संभाव्यता को मान्यता प्रदान करने में निहित है। ऐसे विविधीकरण से यार्न और फैब्रिक जैसे मध्यवर्ती कच्चे माल का उत्पादन करके पटसन उद्योग की मूल्य वसूली में वृद्धि करने में सहायता मिलेगी। जिसका उपयोग विविधीकृत उपयोगों के लिए ठोस उत्पादों के उत्पादन करने के लिए विकेन्द्रीकृत क्षेत्रों द्वारा किया जाएगा जिससे रोजगार बढ़ाने में सहायता मिलेगी। इसके फलस्वरूप किसानों को उनके उत्पाद के लिए अधिक लाभप्रद कीमतें वसूल करने में सहायता मिलेगी क्योंकि पटसन फाइबर की मांग में पुनः वृद्धि होगी। समिति ने मार्जिन धनराशि सहायता तथा सभी संबद्ध क्षेत्रों के साथ जैसे उत्पादकता में सुधार तथा कच्चे पटसन की गुणवत्ताओं सुधार, उद्यमियों तथा अनुसंधान संस्थानों के बीच एक और पारस्परिक संबंध स्थापित करके तथा दूसरी और प्रौद्योगिकी के अंतरण के लिए वित्तीय संस्थानों ओर विपणन माध्यमों के बीच संबंध स्थापित करके उपयुक्त व्यवस्था करके विविधीकरण को सहायता देने की सिफारिश की है। सरकार ने अधिकांश सिफारिशों पर पहले से ही कार्रवाई कर ली है।

हथकरघा उद्योग

5390. श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:
श्री ईश दत्त यादव:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग हथकरघा उद्योग पर निर्भर है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार हथकरघा उद्योग के विकास में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है जिसके परिणामस्वरूप बुनकरों की वित्तीय स्थिति और खराब हो गयी है;

(ग) हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गये है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिये क्या-क्या कदम उठाए गये हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी): (क) वर्ष 1987-88 में की गई हथकरघों से संबंधित गणना के अनुसार कुल 156.1 लाख व्यक्ति हथकरघा उद्योग पर निर्भर थे जो उस समय की जनसंख्या के 2% के बराबर था। उसके बाद अब तक कोई गणना नहीं की गई।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) हथकरघा क्षेत्र के विकास और संवर्धन के लिए भारत सरकार ने कई योजनाएं लागू की हैं इनमें निम्नलिखित योजनाऐं शामिल हैं:—

1. प्रोजेक्ट पैकेज योजना।
2. निस्सहाय बुनकरों के लिए मार्जिन मनी योजना।
3. एकीकृत हथकरघा ग्राम विकास योजना।
4. कार्यशाला-सह-आवास योजना
5. थ्रिफ्ट फंड योजना।
6. समूह बीमा योजना।
7. जनता कपड़ा योजना।
8. विपणन विकास सहायता योजना।
9. राष्ट्रीय डिजाइन संग्रह प्रोग्राम।
10. राष्ट्रीय रेशम सूत बैंक योजना।

इनके अतिरिक्त भारत सरकार ने आठवीं योजना के दौरान लगभग 30 लाख बुनकरों को शामिल करने के लिए 3000 हथकरघा विकास केन्द्रों और 500 उत्कर्ष लेखाई इकाईयों की स्थापना की एक योजना भी आरम्भ की है।

हथकरघा बुनकरों को सस्ता धागे और सूती धागे की आपूर्ति

5391. चौधरी हरमोहन सिंह:
श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हथकरघा बुनकरों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सस्ता धागे और सूती धागे उपलब्ध नहीं कराए जा रहे है;